USE OF INDIAN MUSICAL INSTRUMENTS IN PLAYING THE NATIONAL ANTHEM

*460. SHRI RAGHAVENDRARAO: Will the Minister for HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government propose to introduce the Indian musical instruments in playing the National Anthem; and

(b) whether Government consider the need for Indian instrumental music on various ceremonial occasions other than the Military ones?

THE DEPUTY MINISTER FOR HOME AFFAIRS (SHRI B. N. DATAR): (a) and (b). An instrumental rendering of the National Anthem with Indian instruments is under preparation but it has not yet been finalised. The question whether such instrumental music will be played on any ceremonial occasion and, if so, on what occasions has not been settled.

SHRI RAGHAVENDRARAO: May I know, Sir, how much time it will take?

SHRI B. N. DATAR: It will take a month or so.

SHRI H. C DASAPPA: May I know, Sir, whether the musical instruments that will be selected will be of the different parts of India, north and south?

SHRI B. N. DATAR: The whole question will be considered.

राष्ट्रीय बचत आन्दोलन

*४६१. श्री कृष्णकान्त व्यास : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटी बचतों को एकत्रित करने के बारे में जो लक्ष्यराशि निर्धारित की गई थी क्या उससे भी अधिक राशि किसी राज्य ने एकत्रित कर ली है ;

(ख) क्या इस प्रकार एकत्रित किए गए धन में से इस वर्ष किसी राज्य को स्थानीय विकास के लिए कुछ धन दिया गया है ; और

(ग) क्या किसी राज्य ने केन्द्रीय सरकार से यह प्रार्थना की है कि राष्ट्रीय बचत में से कुछ धन उसको विकास मूलक प्रयोजनों के लिए दिया जाय ?

†[NATIONAL SAVINGS CAMPAIGN

*461. SHRI KRISHNAKANT VYAS: Will the Minister for FINANCE be pleased to state:

(a) whether any State has exceeded the fixed taget for Small Savings Collections;

(b) whether out of the fund so collected any money has been allotted to any State for local developments during this year; and

(c) whether any State has requested the Central Government to allot some money out of the National Savings for development purposes?]

राजस्व तथा प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) से (ग). छोटी बचत संग्रहों के सम्बन्ध में यह व्यवस्था है कि जिस राज्य में निर्धारित रकम से अधिक जितना भी धन संग्रह होता है, वह और साथ ही लक्ष्य के ८० से १०० प्रतिशत के बीच के संग्रह का आधा भाग अगले वर्ष में केन्द्र की ओर से उसी राज्य की स्वीकृत विकास योजनाओं के लिए ऋण के रूप में दे दिया जाता है ।

प्रत्येक राज्य के १९५४-५५ के संग्रह के सुनिश्चित आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुए, किन्तु प्रारम्भिक आंकड़ों से पता चलता है कि आन्ध्र के सिवाय सभी राज्य उक्त वर्ष के छोटी बचत संग्रहों से ऋण पाने के अधिकारी हैं । पिछले वर्ष के संग्रहों के सुनिश्चित आंकड़े मिलने के बाद ही चालू वर्ष में ऋण दिये जायेंगे ।

†English translation.